



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512]
No. 512]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2005/ज्येष्ठ 3, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2005/JYAISTHA 3, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2005

का.आ. 702(अ).—असम के यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) नामक संगठन को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के संबंध में न्याय-निर्णयन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मनीष न्यायमूर्ति श्री आर० एस० सोढ़ी की अध्यक्षता में गठित अधिकरण को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (1) के अधीन भेजे गए संदर्भ के संबंध में पारित उनके आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (4) के अनुसरण में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष:

संदर्भ : अधिसूचना सं० का० आ० 1303 (अ) दिनांक 27.11.2004 - यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम

उपस्थित : श्री पी० पी० मल्होत्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ श्री कैलाश गम्भीर, केन्द्र सरकार के स्थाई कौंसल, भारत संघ की ओर से श्री गौरव शर्मा, श्री यशराज सिंह और श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्तागण।

असम राज्य की ओर से सुश्री कृष्णा शर्मा, श्री एन. जी. जे. लुवांग, और श्री रिकु शर्मा, अधिवक्तागण।

श्री आर० आर० झा, निदेशक (एनई-II), गृह मंत्रालय
श्री एस० टी० वेंकटचेलापति, डेस्क अधिकारी (एन.ई. II), तथा
श्री पी. के. रावत, अनुभाग अधिकारी, गृह मंत्रालय

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एस. सोढी

आदेश

दिनांक: 18 मई, 2005

1. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने दिनांक 27.11.2004 की अधिसूचना सं० का० आ० 1303 (अ) के तहत यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (संक्षेप में उल्फा) तथा इसके विभिन्न गुटों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था। चूंकि केन्द्र सरकार का यह दृढ़ मत था कि उल्फा को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है, इसलिए उसने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक के अंतर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया तथा निदेश दिया कि अधिकरण द्वारा किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यक्षीन, यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।
2. उक्त अधिसूचना के अनुसार उल्फा का घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से असम को भारत से स्वतंत्र कराना तथा भारत-बर्मा क्षेत्र के इसी प्रकार के संगठनों के साथ मिलकर भारत-बर्मा क्षेत्र की आजादी के लिए संघर्ष करना है जिससे असम को भारत से अलग किया जा सके।
3. उपर्युक्त अधिसूचना के परिणामस्वरूप, यह न्याय निर्णय करने के लिए कि क्या उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, दिनांक 23.12.2004 की अधिसूचना सं० का० आ० 1403 (अ) के द्वारा गठित किये गये इस अधिकरण को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत पत्र लिखा गया।
4. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत उल्फा और उसके विभिन्न गुटों को 30 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया गया कि क्यों न उल्फा और उनके विभिन्न गुटों को विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया जाए तथा क्यों न इस घोषणा की पुष्टि करने के लिए आदेश दे दिया जाए। यह निदेश दिया गया कि उक्त संगठन को नोटिसों की तामीली उसके प्रधान कार्यालय पर अथवा उसके किसी

स्पष्ट भाग पर नोटिस की प्रति चिपकाकर की जाए। इसके अतिरिक्त, नोटिसों की तामीली दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों (एक हिन्दी और एक अंग्रेजी में) तथा एक ऐसे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन के द्वारा करने का निदेश दिया गया जिसका असम राज्य में काफी प्रचलन हो तथा साथ ही रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारण के द्वारा और ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें उक्त संगठन/संगम के क्रियाकलाप सामान्य रूप से चलाए जाते हैं, में ढोल बजाकर अथवा लाउडस्पीकों के द्वारा मुनादी करके इन नोटिसों की तामीली करने का निदेश दिया गया।

5. तामील के संबंध में 27 जनवरी, 2005 के शपथ पत्र तथा 7 फरवरी, 2005 के, तामील संबंधी अतिरिक्त शपथ पत्र भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में निदेशक श्री आर० आर० झा, द्वारा प्रस्तुत किए गए। दिनांक 15 जनवरी, 2005 को इंडियन एक्सप्रेस में तथा दैनिक जागरण (हिन्दी दैनिक) में, 14 जनवरी, 2005 को दैनिक जन्मभूमि और 18 जनवरी, 2005 को असोमियन प्रतिदिन में नोटिस प्रकाशित किए गए।

6. श्री जयदीप शुक्ला, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, असम सरकार ने दिनांक 28 जनवरी, 2005 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि 15 जनवरी, 2005 को इंडियन एक्सप्रेस, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में तथा दो स्थानीय असम समाचार पत्रों 'प्रतिदिन' और 'दैनिक जन्मभूमि' में क्रमशः 18 जनवरी, 2005 और 14 जनवरी, 2005 को नोटिस प्रकाशित किया गया। नोटिस का प्रसारण 13 जनवरी, 2005 को दूरदर्शन केन्द्र पर गुवाहाटी के क्षेत्रीय असमी न्यूज बुलेटिन में तथा 19 जनवरी, 2005 को आकाशवाणी, गुवाहाटी पर शाम 6.45 बजे असमी न्यूज बुलेटिन में किया गया। नोटिस की तामीली स्पष्ट स्थानों/हाटों/बाजारों में ढोल बजाकर/लाउडस्पीकर से मुनादी के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेटों/तहसीलदारों के कार्यालयों तथा थानों पर नोटिस चिपकाकर तथा असम के जिलों में स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में ज्ञात उल्फा कार्यकर्ताओं के परिवारों के सदस्यों को नोटिस तामील करके दी गई। इस प्रकार नोटिस तामील किए जाने का कार्य पूरा हो गया है।

7. ऊपर बताए गए अनुसार लिखित रूप में 30 दिनों के अन्दर यह बताने के लिए कि उल्फा को विधिविरुद्ध संगम क्यों न घोषित किया जाए नोटिसें जारी करने के बावजूद, उल्फा की ओर से न तो कोई

उपस्थित हुआ और न ही इसकी ओर से कोई कारण बताया गया। केवल कनक बरूआ का दिनांक 25 जनवरी, 2005 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह बताया गया कि उनके सबसे बड़े बेटे मि0 फिटेन बरूआ ने लगभग 15 वर्ष पूर्व विषम परिस्थितियों में उल्फा की सदस्यता ग्रहण की थी और वह घर से अलग हो गया था तथा इस बारे में उन्हें न तो कोई जानकारी थी और न ही उनकी कोई सहमति थी।

8. केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व श्री पी0 पी0 मल्होत्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ श्री कैलाश गम्भीर, केन्द्र सरकार के स्थाई कौंसल, भारत संघ की ओर से श्री गौरव शर्मा, श्री यशराज सिंह और श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता ने किया था।

9. दिनांक 27.11.2004 की अधिसूचना में निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया गया जिसके आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का विचार बनाया, अर्थात् यह:-

- (i) असम को आजाद कराने के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत की क्षेत्रीय अखण्डता और संप्रभुता को विघटित करने के इरादे से विभिन्न गैर-कानूनी तथा हिंसक वारदातों में संलिप्त हैं;
- (ii) असम को भारत से पृथक करने के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) जैसे अन्य विधिविरुद्ध संगमों के साथ मिलकर कार्य करता है;
- (iii) उल्फा को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किए जाने के दौरान भी अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विधिविरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों में संलिप्त रहे हैं;

10. केन्द्रीय सरकार का यह भी मत था कि विधिविरुद्ध और हिंसक कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) 1.12.2003 से 30.9.2004 तक की अवधि के दौरान हुई हिंसा और आतंकवाद की 273 घटनाएं जिनमें उल्फा का हाथ होने का आरोप है;

- (ii) भारी मात्रा में धन वसूली के तथा पृथकतावादी क्रियाकलापों में संलिप्त होना, फिरौती के लिए व्यपहरण करना और निर्दोष नागरिकों के जीवन को खतरे में डालना;
- (iii) अपने आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखते हुए अपने संवर्ग में नए लोगों को भर्ती करने के लिए चुपचाप परंतु व्यवस्थित अभियान चलाकर निचले स्तर पर संगठनात्मक नेटवर्क को पुनर्गठित करना तथा जिला, आंचलिक और शाखा समितियों का सुधार करने के कार्यक्रम पर अमल करना;
- (iv) संगठन के प्रचार शाखा को सक्रिय करना जिसके द्वारा छिपे तौर पर ऐसी पत्रिकाएं एवं परचे छापे गए हैं जिनमें संगठन के लक्ष्यों एवं केन्द्रीय सरकार के कथित शोषण को प्रमुखता दी गई है और तथाकथित आजादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए जनता की भावनाओं का शोषण किया गया है और इस प्रकार उनकी वफादारी को समाप्त करने की चेष्टा की गई है;
- (v) अपने सदस्यों को पुलिस के मुखबिरों तथा सरकार का सहयोग करने वालों की सूची तैयार करने और उनके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने के लिए उन्हें निशाना बनाने के अनुदेश देना;
- (vi) उल्फा के सैन्य विंग को आम जनता के साथ घुलमिल जाने तथा उन्हें सौंपे गए कार्य करने के लिए अनुदेश देना;
- (vii) पड़ोसी देशों में अनेक प्रशिक्षण शिविर तथा आश्रय स्थलों की स्थापना करना।

11. अतः, केन्द्रीय सरकार का यह मत था कि उक्त कारणों से उल्फा की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए अहितकर थीं और यह एक विधिविरुद्ध संगम है। यदि उल्फा की गतिविधियों पर तत्काल कोई नियंत्रण नहीं किया गया तो यह निम्नलिखित कार्य करने में समर्थ हो जाएगा:-

- (i) अपने काडरों को अपनी पृथकतावादी विध्वंसक तथा हिंसक गतिविधियां बढ़ाने के लिए संचालित करना।
- (ii) भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के विरोधी बलों के साथ दुरभिसंधि करके राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों का खुलेआम प्रचार करना।
- (iii) सिविलियन्स की अधिकाधिक हत्या करने तथा पुलिस एवं सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने में संलिप्त होना।

1568 GI/05-2

(iv) सीमा पर से और अधिक अवैध शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त करना तथा उन्हें लाना।

(v) अपने विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के लिए आम जनता से भारी मात्रा में निधियां तथा अवैध धन संग्रहित करना एवं बलपूर्वक छीनना।

12. न्यायाधिकरण ने, इस मामले में शीघ्रता करने के लिए यह उचित समझा कि साक्ष्य को हलफनामों द्वारा प्राप्त किया जाए। इसके अनुसरण में हलफनामों के आधार पर मुख्यतः छब्बीस गवाहों का परीक्षण किया गया। व्यापक प्रचार-प्रसार के पश्चात 7 जनवरी, 2005 और 25 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में 15 मार्च, 2005 को तेजपुर में, 22 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में, 25 अप्रैल, 2005 को गुवाहाटी में और 27 अप्रैल, 2005 को डिब्रूगढ़ में बैठकें आयोजित की गयीं। इन गवाहों का उपर्युक्त तारीखों पर तेजपुर, नई दिल्ली, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में शपथ के आधार पर पुनः परीक्षण किया गया। सभी गवाह प्रति परीक्षण के लिए उपलब्ध थे परंतु उल्फा संगठन में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तत्पश्चात असम राज्य और केन्द्रीय सरकार ने 27 अप्रैल, 2005 को डिब्रूगढ़ में साक्ष्य बंद कर दिया और 12 मई, 2005 को नई दिल्ली में तर्क-वितर्क सुने गए तथा उन पर निष्कर्ष निकाला गया।

13. केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के संक्षिप्त सार में यह कहा गया है कि जनवरी, 2003 से सितम्बर, 2004 के दौरान उल्फा संगठन द्वारा शुरू की गई हिंसा में 273 घटनाएं शामिल हैं जिनमें कि 24 पुलिस/सुरक्षा कर्मियों सहित 151 लोग मारे गए और 20 लोगों का अपहरण किया गया। हिंसा की इन घटनाओं में राजनीतिक नेताओं, सशस्त्र एवं अर्द्ध सैनिक बलों तथा पुलिस पर हमले, सरकारी कर्मचारियों तथा व्यापारियों का धन वसूली के लिए अपहरण, उच्च शक्ति वाले विस्फोटक यंत्रों का विस्फोट इत्यादि शामिल हैं।

14. गवाहों ने उल्फा के संविधान में अंतर्निहित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों, उसके द्वारा की गई हिंसा की प्रकृति एवं तरीकों तथा दर्ज विभिन्न मामलों के तथ्यों के संबंध में गवाही दी है।

15. गवाहों के साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि उल्फा सक्रिय रूप से कार्रवाई में संलिप्त होकर अपने संविधान में अंतर्निहित मुख्य लक्ष्य को पाने की दिशा में अग्रसर है। रिकार्ड के

तथ्य उनके विधिविरुद्ध क्रियाकलाप दर्शाते हैं जिनमें कि हत्या, अपहरण, जबरन धन वसूली पुलिस/सुरक्षा कर्मियों और सशस्त्र बलों पर हमले शामिल हैं। उपर्युक्त कार्यकलाप दर्शाते हैं कि उल्फा अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के प्रति अभी भी सक्रिय तथा प्रतिबद्ध है। इसके द्वारा बड़े पैमाने पर दहशत फैलाने के गंभीर प्रयास किये गए हैं। केन्द्र सरकार तथा असम सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी गई। अतः इसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

16. इन मामलों को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है कि केन्द्र सरकार का इस निष्कर्ष पर पहुंचना पूर्णतः न्यायसंगत था कि उल्फा के काडरों में अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए बढ़ते विधिविरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों तथा उनकी पुनः सक्रियता को रोकने के लिए उल्फा को तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक था। परिस्थितियों की समग्रता और दर्ज साक्ष्यों से मैं संतुष्ट हूँ कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 में प्रयुक्त शक्तियों के अनुरूप दिनांक 27 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं० का०आ० 1303 (अ) द्वारा उल्फा को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त कारण विद्यमान है। तदनुसार भारत सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में की गई घोषणा की संपुष्टि की जाती है। यह घोषित किया जाता है और निर्णय किया जाता है कि केन्द्र सरकार के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं जिनके कारण वह अधिनियम की धारा 3 के उप खंड (3) के उपबंध के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करे।

हस्ताक्षर/-

18 मई, 2005

(आर० एस० सोढी)
पीठासीन अधिकारी
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

[फा. सं. 11011/45/2004-एनई III]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2005

S.O. 702(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice R.S. Sodhi, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association, namely the United Liberation Front of Asom (ULFA) Organisation of Assam as unlawful, is published for general information.

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

In re : Notification No. S.O. 1303(E) dated 27-11-2004—United Liberation Front of Asom.

Present : Mr. P.P. Malhotra, Additional Solicitor General with Mr. Kailash Gambhir, Central Govt. Standing Counsel, Mr. Gaurav Sharma, Mr. Yasraj Singh and Mr. Shailendra Sharma, Advs. for Union of India.

Ms. Krishna Sharma, Mr. N.G.J. Luwang and Mr. Riku Sharma, Advs. for the State of Assam.

Mr. R.R. Jha, Director (NE-II), Ministry of Home Affairs, Mr. S.T. Venkayachalapati, Desk Officer (NE-II) and Mr. P.K. Rawat, Section Officer, Ministry of Home Affairs.

Coram : Hon'ble Mr. Justice R.S. Sodhi

ORDER

18th May, 2005

1. The Central Government vide a Notification bearing No. S.O. 1303(E) dated 27th November, 2004, in pursuance to the powers conferred under Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as "the Act") declared the United Liberation Front of Asom (for short "ULFA") along with all its factions, wings and front organisations to be as unlawful associations. The Central Government being of the firm opinion that it was necessary to declare ULFA to be an unlawful Association with immediate effect, exercised its powers under the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Act and directed that the Notification, subject to any order that may be made by the Tribunal, shall have effect from the date of its publication in Official Gazette.

2. As per the Notification, ULFA has its professed aim "the liberation" of Assam from the Indian Union through an armed struggle, in alliance with other armed secessionist organizations of the North East Region as well as to struggle for the national liberation of the Indo Burma region. In alliance with like minded organizations of that region and thereby have the secession of Assam from the Indian Union.

3. Consequent upon the Notification referred to above, reference was made under Section 4(1) of the Act to this Tribunal constituted vide Notification bearing No. S.O. 1403(E) dated 23rd December, 2004, for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the ULFA as an unlawful association.

4. Notices were directed to be issued to the ULFA and various wings thereof under sub-section (2) of Section 4 of the Act to show cause within 30 days why ULFA be not declared an unlawful association. It was directed that notices be served upon the said organisation at its principal office or by affixing a copy of the notice at some conspicuous part thereof. In addition, notices were directed to be served by publication in two National Newspapers (one in Hindi and one in English) and in one vernacular newspaper, having circulation in the state of Assam as well as by broadcasting on radio and telecasting on Doordarshan and by proclaiming by beat of drum or by means of loudspeakers in the areas in which activities of aforesaid organization/association are ordinarily carried on.

5. Affidavits of service dated 27th January, 2005 and additional affidavit of service dated 7th February, 2005 were filed by Mr. R.R. Jha, Director to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi. Notices were published in the Indian Express on 15th January, 2005, Dainik Jagran (Hindi Daily) on 15th January, 2005, Dainik Janambhumi on 14th January, 2005 and Asomia Pratidin on 18th January, 2005.

6. Mr. Joydeep Shukla, Extra Assistant Commissioner, Govt. of Assam has filed affidavit dated 28th January, 2005. It is stated in the affidavit that notice was published in the 'Indian Express' on 15th January, 2005, Hindi daily 'Dainik Jagran' on 15th January, 2005, and two vernacular Assamese newspapers 'Pratidin' and 'Dainik Janmabhumi' on 18th January, 2005 and 14th January, 2005 respectively. The notice was also telecast on Doordarshan Kendra, Guwahati's regional Assamese News Bulletins on 13th January, 2005 and also broadcast in the Assamese News Bulletin at 6.45 p.m. of

the All India Radio, Guwahati, on 19th January, 2005. The notice was also served by way of beating of drum/announcement through loudspeakers within conspicuous places/hats/bazars, pasting of notice at the offices of District Magistrates/ Tehsildars and the Police Stations and service on family members of known ULFA activists in presence of independent witnesses in the districts of Assam. Thus the service is complete.

7. Despite publication and service of notice, as aforesaid, to show cause in writing within 30 days, as to why ULFA should not be declared as an unlawful association, neither anyone has put in appearance on behalf of ULFA nor any cause shown by anyone on its behalf. Only one letter dated 25th January, 2005 was received from Mr. Kanak Ch. Boruah wherein it is stated that his son, Mr. Fiten Boruah, left home and joined ULFA without his knowledge or consent about 15 years back.

8. The Central Government was represented through Mr. P.P. Malhotra, Additional Solicitor General, Mr. Kailash Gambhir, Standing Counsel, Mr. Shailendra Sharma, Mr. Gaurav Sharma and Mr. Yash Raj Singh, Advocates and the State of Assam by Ms. Krishna Sharma, Mr. Riku Sharma and Mr. J.G.J. Luwang, Advocates.

9. In the notification dated 27-11-2004, the grounds mentioned, on which the Central Government formed the opinion to declare ULFA as an unlawful association, are that it has—

- (i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;
 - (ii) aligned itself with other unlawful associations like the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) to secede Assam from India;
 - (iii) in pursuance of its aims and objectives engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association;
10. The Central Government was further of the opinion that the unlawful and violent activities include—
- (i) 273 violent incidents, which are attributed to ULFA during the period from 1st January, 2003 to 30th September, 2004;
 - (ii) indulging in a spate of extortion and secessionist activities and endangering lives of innocent citizens, in addition to its acts of kidnapping for ransom;
 - (iii) embarking on a programme of restructuring its organizational network at grass root level by launching a quiet but systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district anchalik and sakha committees, while continuing its violent and insurgent activities;
 - (iv) making publicity wing of the organization active, which has published clandestine leaflets, magazines highlighting the goal of the outfit, alleged exploitation by the Central Government and exhorting the people to join the so-called liberation struggle and thereby subverting their loyalties;
 - (v) instructing its cadres to compile the list of police informers and government collaborators and to identify targets for retaliatory action against them;
 - (vi) instructing the army wing of ULFA to mingle with the common people and execute assigned tasks;
 - (vii) establishing sanctuaries and a number of training camps in neighbouring countries.

11. The Central Government was also of the opinion that for the reasons mentioned above, the activities of ULFA were detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association; if there is no immediate curb and control of unlawful activities of the ULFA, it may take the opportunity to—

- (i) mobilize its cadres for escalating its secessionist, subversive and violent activities.
- (ii) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;
- (iii) indulge in increased killings of civilians and targeting of police and security forces personnel;
- (iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the border;
- (v) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities;

12. The Tribunal, in order to expedite the matter, thought it fit to receive evidence by way of affidavits. Pursuant thereto twenty-six witnesses were examined in-chief on affidavit. To facilitate cross-examination of these witnesses, sittings were held after wide publication on 7th January, 2005 and 25th February, 2005 at New Delhi, on 15th March, 2005 at Tezpur, on 22nd March, 2005 at New Delhi, on 25th April, 2005 at Guwahati and on 27th April, 2005 at Dibrugarh. The witnesses were

re-examined on oath at Tezpur, New Delhi, Guwahati and Dibrugarh on the dates mentioned above. All the witnesses were available for cross-examination, but no one from the ULFA organization chose to do so. The evidence was thereafter closed by the State of Assam and the Central Government on 27th April, 2005 at Dibrugarh and arguments were heard and concluded on 12th May, 2005 at New Delhi.

13. In brief resume of facts, tendered by the Central Government, it is stated that the violence unleashed by the ULFA outfit during January, 2003 to September, 2004 includes 273 incidents during which 151 persons, including 24 police/security personnel, were killed and 20 persons kidnapped. The incidents include attack on political leaders, armed and para-military forces and police, kidnapping of Government officials and businessmen for ransom, explosion of high power explosive devices etc.

14. The witnesses have deposed to the aims and object of ULFA as per its constitution, nature and manner of violence indulged by it and to the facts of various cases registered.

15. From a careful analysis of the deposition of witnesses, it would be seen that the ULFA has been actively pursuing and indulging in activities with a view to fulfil its main object as per its constitution. The evidence on record shows the unlawful activities, namely, killings, kidnapping, extortion, attack on police/security personnel and armed forces. The aforesaid activities demonstrate that ULFA continues to be active and committed to its aims and objects. There have been serious attempts to cause widespread panic. The evidence led by the Central Government and the Government of Assam has gone unchallenged before the Tribunal. Its credibility, therefore, cannot be doubted.

16. In this view of the matter, I am of the opinion that the Central Government was fully justified in reaching a conclusion that the declaration of ULFA as an unlawful association with immediate effect was necessary to prevent unlawful and violent activities and remobilization of ULFA cadres in furtherance of its aims and objects. From the totality of the circumstances and evidence on record. I am satisfied that there is sufficient cause for declaration of ULFA as an unlawful association by Notification No. S.O. 1303(E) dated 27th November, 2004, pursuant to powers exercised under Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Accordingly, the declaration made by the Government of India in the said Notification is confirmed. It is declared and held that circumstances existed for the Central Government to invoke its powers under the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Act for the Notification to be made applicable with immediate effect.

May 18, 2005

R. S. Sodhi, Presiding Officer,
The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal
[F.No. 11011/45/2004-NE.III]
RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.